

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या: 957
18 सितंबर, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान स्वास्थ्य काड

957. डॉ॰ मोहम्मद जावेद:

श्री गोपाल जी ठाकुर:

श्री रामचरण बोहरा:

श्री वी॰ वैथीलगम:

श्री धमवीर सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी बीपीएल/पात्र परिवारों को आयुष्मान स्वास्थ्य काड/ई-काड वितरित किए है और यदि हां, तो विशेषकर बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पुदुचेरी सहित कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों म बडी संख्या म पात्र लाभार्थियों को इस योजना के कवरेज से बाहर रखा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कब तक शामिल किए जाने का संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है कि वास्तविक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिले;

(ङ) आयुष्मान भारत योजना के अंतगत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए क्या मापदंड तय किए गए है; और

(च) हरियाणा और दिल्ली म इस योजना के तहत संलग्न निजी और सरकारी अस्पतालों को संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) -2011 के आकडों के अनुसार आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) ग्रामीण क्षेत्रों म वंचित परिवारों और चिन्हित व्यावसायिक श्रेणियों के कामगारों के परिवारों को कवर करती है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे सभी लाभार्थी परिवार जो एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार लक्षित समूहों में शामिल नहीं होते हैं, को भी एबी- पीएमएसएवाई के अंतर्गत कवर किया गया है। एबी- पीएमएसएवाई एक पात्रता आधारित योजना है और सभी पात्र परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के दिन से कवर होते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पंजीकरण या नामांकन को जरूरत नहीं है।

तथापि, आसानी से लाभ लेने सुविधाजनक बनाने के लिए, लाभार्थी के सत्यापन के पश्चात, ई- काड जारी किए जाते हैं। दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार योजना के अंतर्गत 12.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है।

बिहार में, दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार, 53.9 लाख लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। लाभार्थियों को जारी ई- काड का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पात्र लाभार्थी योजना के लाभों से वंचित न रहे, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को मिशन मोड में लाभार्थी को पहचान करने का निदेश दिया गया है। एसएचए को परामर्श भी दिया गया है कि वे योजना के लाभार्थियों को पहचान के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में सभी अंतरंग रोगियों को जांच करें।

इसके अलावा, लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत अपने हकों और अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने और जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक मिडिया एवं आऊटरील रणनीति का अनुसंधान किया गया है। इसमें मिडिया वाहनों जैसे आऊटडोर मिडिया का प्रयोग विभिन्न रेलवे स्टेशनों के टिकट काउन्टर्स, डिजिटल डिस्प्ले, मुख्य बस स्टेशनों पर घोषणाएं, यात्री ट्रेन को ब्रान्डिंग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस कवरेज प्रिंट मिडिया में ऑप एड और विज्ञापनस रेडियों अभियान, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थी टेस्टिमोनियल्स का प्रसारण, एसएमएस के जरिए बड़े पैमाने पर संदेश देना, पारम्परिक मीडिया आदि आधारित है।

उपचार लेने से पहले लाभार्थी को पहचान स्थापित करने/ प्रभावित करने के लिए एक पहचान प्रणाली लागू है। लाभार्थी को पहचान सफल प्रमाणन के उपरांत सेवाओं को व्यवस्थित प्रदानगी के लिए विशिष्ट आईडी के साथ एक पेपर आधारित ई- काड प्रदान किया जाता है।

(ङ) दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार, योजना के अंतर्गत अस्पतालों में 1.23 करोड़ से अधिक लाभार्थी भर्ती हो चुके हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत नए लाभार्थी परिवारों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, छूटे गए परिवारिक सदस्यों को मौजूदा लाभार्थी परिवार में जोड़ा जा सकता है।

(च) दिनांक 14/9/2020 को स्थितिनुसार हरियाणा में निजी क्षेत्र के 374 अस्पतालों सहित 545 अस्पताल पैनलबद्ध हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एबी- पीएमएसएवाई योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। तथापि, चूंकि संपूर्ण देश में लाभों को पोर्टबिलिटी है, दिल्ली में 35 निजी अस्पतालों सहित 66 अस्पताल अन्य राज्यों से आए लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध हैं।

एबी- पीएमएसएवाई के अंतगत लाभार्थियों को जारी ई- कार्डों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा (दिनांक 14/09/2020 को स्थितिनुसार)		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	ई- कार्ड जारी (लाख म) *	अधिकृत अस्पतालीकरण (लाख म)
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.15	0.002
आंध्र प्रदेश*	-	8.88
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.018
असम	122.78	1.496
बिहार	53.9	2.068
चंडीगढ़	0.51	0.059
छत्तीसगढ़	30.06	10.674
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	4.02	0.53
गोवा	0.22	0.101
गुजरात	72.85	19.056
हरियाणा	22.5	1.646
हिमाचल प्रदेश	8.47	0.707
जम्मू और कश्मीर यूटी	11.08	0.891
लद्दाख यूटी	0.32	0.008
झारखंड	87.99	6.267
कनाटक	97.83	9.143
केरल	64.51	13.573
लक्षद्वीप	0.02	0
मध्य प्रदेश	145.7	4.473
महाराष्ट्र	68.99	3.339
मणिपुर	2.45	0.213
मेघालय	15.73	1.761
मिजोरम	3.52	0.439
नगालड	2.43	0.149
पुडुचेरी	1.23	0.031
पंजाब	44.24	3.933
राजस्थान*	-	9.846
सिक्किम	0.32	0.021
तमिलनाडु	247.27	16.912
त्रिपुरा	11.45	0.718
उत्तर प्रदेश	96.16	4.51
उत्तराखंड	38.91	2.126
कुल संख्या	1,255.62	123.591

* उपरोक्त सूचना पीएमएसएवाई आईटी प्लेटफॉर्म पर जारी ई- कार्डों के साथ- साथ राज्य योजनाओं के सहयोग से पीएमएसएवाई का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी कार्डों से संबंधित है।